आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 18.03.2026 समय 1305

मुख्य समाचार :–

- राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के तत्वावधान में श्रीलंका के 40 सिविल सेवा के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया। विभिन्न गतिविधियों और नवाचारों की जानकारी ली।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एआई युग में मीडिया शिक्षा को समयानुकूल बनाने पर जोर दिया।
- अवैध खनन पर हरिद्वार जिला प्रशासन सख्त। चौदह स्टोन क्रेशर सील, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना।
- पौड़ी जिले में घरेलू गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए 60 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के तत्वावधान में श्रीलंका के 40 सिविल सेवा के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, व्यवस्थाओं और नवाचारों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व डीआईजी राजकुमार नेगी ने प्रतिनिधिमंडल को प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल को आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम की अवधारणा व संरचना, आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा के बाद पुनर्वास व पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखण्ड में अपनाए जा रहे तकनीकी मॉडल, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जोखिम आकलन पद्धतियों और सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से जानकारी ली और इसे अपने देश में लागू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संवाद और अध्ययन भ्रमण बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये विभिन्न देशों के बीच ज्ञान, अनुभव एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान का सशक्त माध्यम बनते हैं।

राज्यपाल बैठक

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के मीडिया एवं जनसंचार विभागों के विभागाध्यक्षों और डीन के साथ बैठक की। बैठक में "एआई युग और डिजिटल सूचना पारिस्थितिकी तंत्र में मीडिया शिक्षा, चुनौतियाँ, नैतिकता और अवसर" विषय पर विचार–विमर्श

किया गया। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि आज के समय में एआई और डिजिटल मीडिया ने सूचना देने और पाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है, इसलिए मीडिया शिक्षा को भी समय के अनुसार बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में फेक न्यूज और गलत जानकारी बड़ी चुनौती बन गई है। इससे निपटने के लिए छात्रों को सही प्रशिक्षण देना जरूरी है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से कहा कि अपने पाठ्यक्रम में एआई, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल सुरक्षा और फैक्ट–चेकिंग जैसे विषय शामिल करें। राज्यपाल ने विभागाध्यक्षों से कहा कि वे पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के उपायों पर भी विचार करें। उन्होंने कहा कि एआई के सदुपयोग के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका सही दिशा में उपयोग कर सकें। दून विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए डीन और विभागाध्यक्षों ने वर्तमान समय में एआई के बढ़ते प्रभाव के बारे अपने–अपने विचार रखे।

कृषि मंत्री

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन किया और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने घेरबाड़ कार्यों के लिए स्वीकृत 90 करोड़ रुपये में से राज्य को प्राप्त 25 करोड़ रुपये के संबंध में जिलावार प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही शेष राशि की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली आवश्यक औपचारिकताएं भी समयबद्ध रूप से पूरी करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। कषि मंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 20 करोड़ रुपये के बजट के अंतर्गत घेरबाड़ कार्यों की जिलेवार कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया और कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

स्टोन क्रशर सील

हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध खनन और भंडारण पर सख्त रुख अपनाते हुए हरिद्वार और लक्सर तहसील क्षेत्रों में 14 स्टोन क्रशर को सील किया है, जबकि उनके ई–रवन्ना पोर्टल को भी अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने छापेमारी के दौरान कई क्रशरों में अनियमितताएं पाए जाने पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के अनुसार प्रशासन को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध खनन और भंडारण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रवर्तन दल ने यह कार्रवाई की है।

निरीक्षण

पौड़ी जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग ने व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। अभियान के तहत जिले में 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 16 गैस गोदाम और 44 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल रहे। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि खाद्य निरीक्षकों ने अपने–अपने क्षेत्रों में गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है और आगे भी इस प्रकार के निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।

व्यावसायिक सिलेंडर

सरकार के दिशा–निर्देशों के बाद पिथौरागढ़ जिले में भी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बताया कि जिले के लिए तीन प्रतिशत व्यावसायिक एलपीजी का कोटा निर्धारित किया गया है, जिससे होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के सुचारु वितरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि आपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे।

कम्प्यूटर लैब

हरिद्वार जिले की रुड़की तहसील में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वी–मार्क इण्डिया द्वारा स्थापित अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया गया। यह पहल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर हरिद्वार जिला प्रशासन और आईआईटी रूड़की के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत आईआईटी रूड़की के प्रख्यात प्रोफेसरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और पाठ्यक्रम पूरा होने पर विद्यार्थियों को आईआईटी रूड़की की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि यह पहल सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी और उन्हें डिजिटल भारत के निर्माण में सहभागी बनाएगी।

पर्यटन / प्रस्ताव

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। समिति ने पर्यटक आवास सांकरी, वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर, इको टूरिज्म सेंटर और जलक्रीड़ा केंद्र मनेरी के अनुबंध विस्तार को स्वीकृ

ति दी। तिलोथ में घाट विकास, चेंजिंग रूम और रेलिंग निर्माण कार्यों को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा खरसाली एडवेंचर सेंटर और डामटा के पर्यटन सूचना केंद्र के संचालन के लिए निविदा आमंत्रित करने पर सहमति बनी।